उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण

डॉ0 अवध बिहारी सिंह

मुक्त बाजार तथा आर्थिक उदारीकरण नीति से भारतीय उच्च षिक्षा व्यवस्था काफी प्रभावित हुयी है जिसके चलते स्ववित्त पोषित षिक्षा व्यवस्था के तहत उच्च षिक्षा के निजीकरण को बढावा मिल रहा है। इससे पूँजीपतियों के लिए कालेधन के निवेष एवं मुनाफा खोरी का अवसर मिलता जा रहा है। उच्च षिक्षा में प्रत्यक्ष विदेषी पूँजी निवेष के निर्णय ने भारत में उच्च षिक्षा की विदेषी डिग्री बेचने का रास्ता साफ कर दिया है। इन नीतियो से षिक्षा की समानता के अधिकार, षिक्षा सबका अधिकार जैसे लोक कल्याणकारी योजना को अमल मे लाने के बजाय सरकार ने उच्च षिक्षा को पूँजीपतियों के दुकानों के हवाले कर दिया है। इससे सरकारी व्यवस्था के तहत चलने वाले कालेजों एवं विष्वविद्यालयों के प्रति युवाओं का आकर्षण कम होता जा रहा है। अच्छी खासी पूँजी खर्च करके बनाये गये आधुनिक सूचना तकनीक से लैष, नवीनतम सुख–सुविधा वाले आलीषान निजी संस्थानों /कालेजों /विष्वविद्यालयों सें उच्च षिक्षा प्राप्त करना युवाओं का सपना बनता जा रहा है। इस सपना को साकार करने हेतु उन्हे अच्छी खासी रकम अदा करनी पड़ रही है । बड़े बड़े षहरो में ऊँची कीमत पर उच्च षिक्षा को बेचने की दुकानें लगातार खुलती जा रही हैं। षिक्षा को एक उत्पाद के रूप में बेचने हेतु लगातार मीडिया में इन संस्थानों द्वारा विज्ञापन भी दिया जा रहा है । इस तरह से आम व्यवसाय की तरह ही उच्च षिक्षा का व्यवसायीकरण लगातार चल रहा है।